

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3409
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का जीवीए

3409. श्री आशीष दुबे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2023-24 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) कितना है और वर्ष 2014-15 से इसकी तुलना क्या है;
- (ख) अप्रैल, 2014 से मार्च, 2025 तक उक्त क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इक्विटी आवक हुआ;
- (ग) वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का हिस्सा कितना है;
- (घ) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा कितना है;
- (ङ) वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में विभिन्न राज्यों का योगदान कितना रहा है;
- (च) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कितनी है और दिसम्बर, 2025 तक उक्त इकाइयों की निवेश प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा क्या है;
- (छ) जबलपुर में कितने खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और
- (ज) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत कोई इकाई स्थापित करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)**

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2.24 लाख करोड़ रुपये (पहले संशोधित अनुमान के अनुसार) है, जबकि वर्ष 2014-15 में यह 1.34 लाख करोड़ रुपये था।

(ख): उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2014 से मार्च 2025 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इक्विटी अंतर्वाह 7334.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

(ग): वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 20.4% है।

(घ): वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का रोजगार हिस्सा 12.83% है।

(ङ): वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में राज्यों का योगदान विभिन्न कारकों जैसे कि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उनका मजबूत कृषि आधार, औद्योगिक अवसंरचना,

खाद्य नीतिगत समर्थन, आदि से संचालित है। वर्ष 2023-24 के लिए एएसआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य-वार पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां **अनुबंध-I** में दी गई हैं।

(च) से (ज): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत, दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 7462.77 करोड़ रुपये के निवेश के साथ योजना के अंतर्गत कुल 274 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। उक्त इकाइयों की निवेश प्रतिबद्धताओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। इसके अलावा, जबलपुर में कोई खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है और पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत कोई नया आवेदन लंबित नहीं है।

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का जीवीए" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3409 के भाग (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पंजीकृत क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगी इकाइयाँ

क्र.सं.	राज्य	इकाइयों की संख्या (एएसआई के अनुसार *)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5
2	आंध्र प्रदेश	5237
3	अरुणाचल प्रदेश	48
4	असम	1798
5	बिहार	1020
6	चंडीगढ़	19
7	छत्तीसगढ़	2525
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	49
9	दिल्ली	142
10	गोवा	97
11	गुजरात	2691
12	हरियाणा	998
13	हिमाचल प्रदेश	179
14	जम्मू-कश्मीर	192
15	झारखंड	270
16	कर्नाटक	2448
17	केरल	1692
18	लद्दाख	8
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	1120
21	महाराष्ट्र	2898
22	मणिपुर	42
23	मेघालय	31
24	मिजोरम	29
25	नागालैंड	18
26	ओडिशा	1403
27	पुदुचेरी	69
28	पंजाब	3401
29	राजस्थान	1000
30	सिक्किम	16
31	तमिलनाडु	4911
32	तेलंगाना	3959
33	त्रिपुरा	136
34	उत्तर प्रदेश	2955
35	उत्तराखंड	372
36	पश्चिम बंगाल	2267
	कुल	44,032

स्रोत: *वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24,

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का जीवीए" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3409 के भाग (च) से (ज) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31.12.2025 तक पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

राज्य	अनुमोदित स्थानों की संख्या	प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रु. में)
आंध्र प्रदेश	36	1043.89
असम	4	47.74
बिहार	7	488.66
छत्तीसगढ़	1	40.93
गोवा	1	17.99
गुजरात	31	1343.76
हरियाणा	9	74.53
हिमाचल प्रदेश	4	10.66
जम्मू और कश्मीर	2	61.13
झारखंड	2	11.76
कर्नाटक	21	271.58
केरल	10	165.91
मध्य प्रदेश	10	468.15
महाराष्ट्र	41	941.98
उड़ीसा	6	182.77
पंजाब	9	126.31
राजस्थान	6	244.82
तमिलनाडु	19	389.53
तेलंगाना	13	200.89
उत्तर प्रदेश	26	1052.10
उत्तराखंड	7	116.05
पश्चिम बंगाल	9	161.63
कुल	274	7462.77